

भारत के आर्थिक विकास में क्षेत्रवार भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of Sectoral Role in India's Economic Development

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

सारांश

एंगस मैडीसन की पुस्तक 'द वर्ल्ड इकॉनोमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स' के अनुसार 1ई0 सन् में विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा 52.9 प्रतिशत था जो 1000 ई0 सन् में घटकर 33 प्रतिशत रह गया। समय के साथ-साथ दुनिया में बदलाव आया और भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में 6-7 प्रतिशत हिस्सा ही रह गया। जिसके परिणामस्वरूप 'सोने की चिड़िया' कहलाने वाले देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ने के साथ पूँजी निर्माण की दर बहुत कम रह गई। क्षेत्रवार श्रमशक्ति की क्रियाशीलता में कृषि क्षेत्र आज भी सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है।

According to Angus Maddison's book 'the world economy historical statistics' the share of the Indian economy in the world economy was 52.9 percent in in 1 A.D. which decreased to 33 percent in 1000 A.D. the world changed with the passage of time and but the share of the Indian economy remained only 6-7 percent of the world economy . As a result poverty and unemployment increased and the rate of capital formation was very low in the country called ' Golden Bird ' sector wise the agriculture sector is still the most employment providing sector in the workforce.



हरवीर सिंह चौधरी

सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
जे0वी0 जैन कालेज,
सहारनपुर, उ०प्र० भारत

मुख्य शब्द : आर्थिक विकास, क्षेत्रवार योगदान, बेरोजगारी, भारतीय कृषि, श्रम कानून ।

Economic Development, Sectoral Role, Unemployment, Indian Agriculture, Labour Laws.

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है अन्य विकासशील देशों की भाँति भारत में विकास की अपार सम्भावना है वहीं कुछ समस्याएँ भी हैं। जिनमें पूँजी निर्माण की धीमी दर और पूँजी की कमी से विकास योजनाओं के संचालन में कठिनाई के साथ-साथ गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएँ प्रमुख हैं। स्वतन्त्रता पश्चात भारत सरकार ने विकास हेतु 1950 में योजना आयोग का गठन किया। हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय (1951-1956) जो कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी से आरम्भ किया गया जिसकी कुल विकास दर 3.6 प्रतिशत रही दूसरी योजना (1956-61) भारतीय सांख्यिकी विशेषज्ञ-पी0सी0 महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जो औद्योगिक विकास केन्द्रित थी जिसकी विकास दर 4.1% थी। आयोजन की यह यात्रा अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) पूर्ण कर चुकी है। इस अन्तराल में वरीयता और लक्ष्य परिवर्तन होती रही है। वहीं JAN 2015 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा इस आयोग को नए परिदृश्य में अप्रासंगिक मानते हुए समाप्त कर नवीन सुधारों के साथ नए नाम NITI आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) की स्थापना की गई नीति आयोग अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा विकास की गति को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिकल्पनाएँ

1. क्षेत्रवार सन्तुलित विकास नहीं हो रहा है।
2. कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कम हुआ है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान और संभावनाओं का अध्ययन करना।
2. रोजगार के अवसर तलाशना।
3. आर्थिक विकास का अध्ययन करना।

CSO/NSSO व अन्य विश्वसनीय स्रोतों से द्वितीय समकों का यथा स्थान उपयोग और विश्लेषण किया गया है।

भारत जैसे विकासशील देशों में सबसे बड़ी समस्या अधिक जनसंख्या दबाव के कारण तेजी से बढ़ती बेरोजगारी है। CMIE की भारत में बेरोजगारी की दर (दिसम्बर 2020) रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 9.06% है। यह विशेष वर्ष है क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसके चलते एक लम्बी समयावधि के लिए लगभग सभी आर्थिक क्रियायें बंद रही।

पाँच सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाले राज्य

क्र० सं०	राज्य	बेरोजगारी दर (% में)
1	हरियाणा	32.5
2	राजस्थान	28.2
3	त्रिपुरा	18.2
4	जम्मू और कश्मीर	16.6
5	उ० प्र०	14.9

स्रोत: CMIE Dec 2020 रिपोर्ट

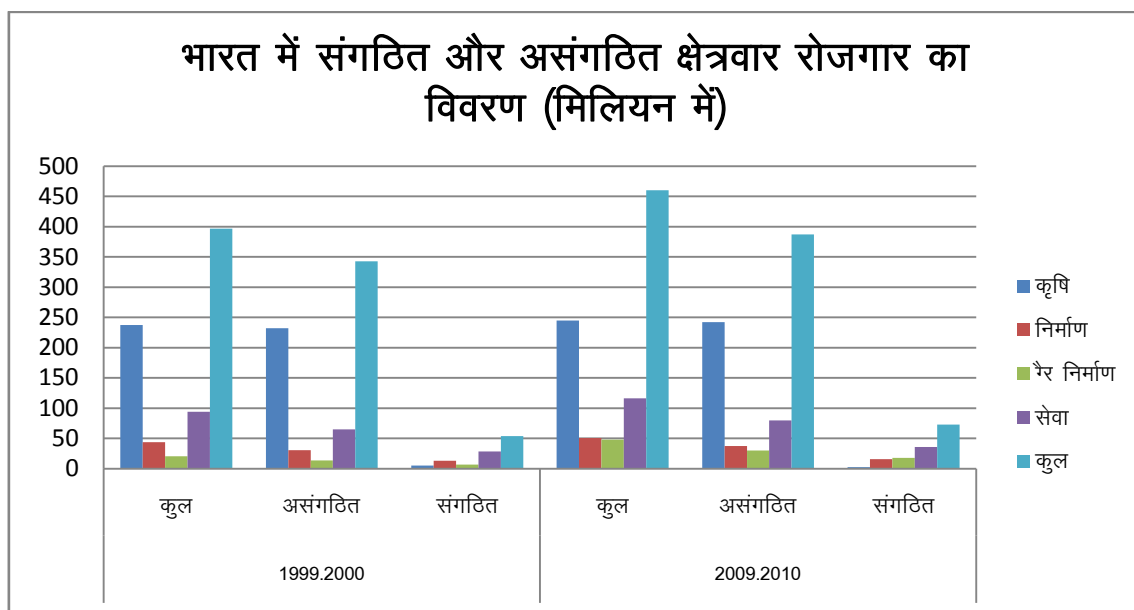
अधिक बेरोजगारी दर वाले ये राज्य कृषि पृष्ठभूमि वाले हैं लेकिन अनेक विद्वान बेरोजगारी की बढ़ती दर का प्रमुख कारण श्रम कानूनों को मानते हैं। पड़ोसी देश चीन की तुलना में भारत में श्रम कानून जटिल और अस्पष्ट हैं। भले भारत लोकतान्त्रिक देश होने के कारण चीन जैसे काठोर कानून नहीं बना सकता इसके उपरान्त इस अस्पष्ट नीति ने अब तक FDI को

हत्तोहित किया है। प्रवर साहू के अनुसार 'भारत में केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगभग 250 श्रम नियम हैं और वैश्विक निर्माण कम्पनियों भारतीय श्रम कानूनों को अत्यधिक जटिल और प्रतिबंधात्मक मानती हैं। 'द इकोनोमिस्ट' के अनुसार भारतीय श्रम कानून लोचहीन और प्रतिबंधात्मक हैं। खराब बुनियादी ढांचे के संयोजन में यह बेरोजगारी की स्थिति का कारण हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायिक विनियमों की सुधार सूची में भारत विगत वर्ष की तुलना में 14 पायदान चलकर 63 वें स्थान पर आया है यह प्रगति आशाजनक है लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर करते हैं। इस व्यवस्था को संगठित और असंगठित दो भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों क्षेत्रों की प्रकृति भिन्न होती है। जिन उपक्रम का संचालन, नियमन, पंजीकरण, सरकार द्वारा होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, और शेष ऐसे व्यवसायों और उत्पादन ईकाइयों को जिनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है उनका पंजीकरण सरकार के किसी कार्यालय में नहीं होता उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र में संचालित उपक्रमों में लगे सभी व्यक्तियों के लिये सरकार न्यूनतम मजदूरी, श्रम के घंटे वेतन बढ़ोत्तरी, कार्य स्थल पर अवश्यक सुविधाओं के नियम तय करती है जिनका सभी को पालन करना होता है। वहीं असंगठित क्षेत्र में इस तरह के कोई नियम नहीं होते। नियोक्ता अपनी सामर्थ्य और सुविधा अनुसार नियम तय कर लेता है। संगठित क्षेत्र का विस्तार किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है।

भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रवार रोजगार का विवरण (मिलियन में)

क्षेत्र	1999-2000			2009-2010		
	कुल	असंगठित	संगठित	कुल	असंगठित	संगठित
कृषि	237.67	232.2	5.47	244.85	242.11	2.74
निर्माण	44.05	30.92	13.13	50.74	37.71	16.03
गैरनिर्माण	20.84	13.89	6.95	48.28	30.36	17.92
सेवा	94.20	65.07	28.57	116.34	80.15	36.19
कुल	396.76	342.64	54.12	460.22	387.34	72.88

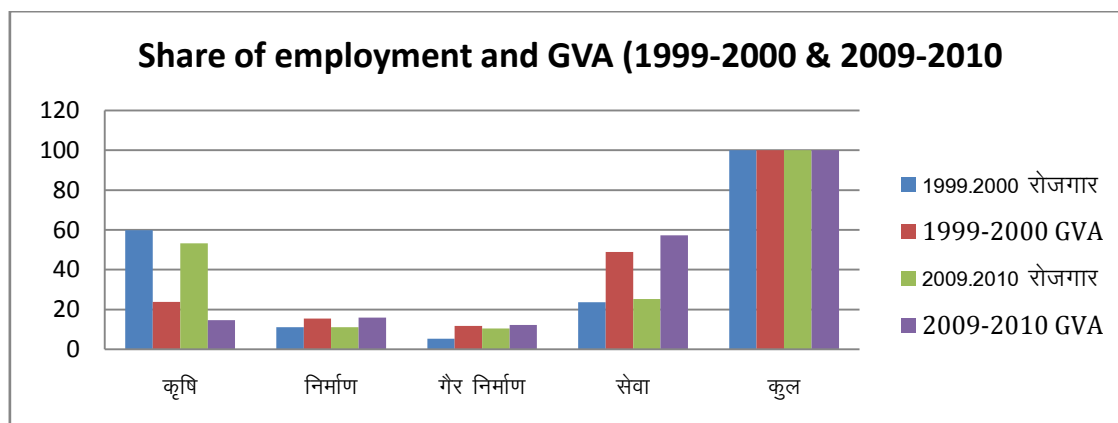
Source- NSSO 66th round on unemployment and employment 2009-10



(Share of employment and GVA (1999-2000 & 2009-2010))

क्षेत्र	1999-2000		2009-2010	
	रोजगार	GVA	रोजगार	GVA
कृषि	59.9	23.8	53.20	14.60
निर्माण	11.1	15.5	11.03	15.90
गैर निर्माण	5.3	11.8	10.49	12.22
सेवा	23.7	48.9	25.28	57.30
कुल	100	100	100	100

Source:- CSO &NSSO Employment & unemployment survey report 2009-10



उद्योगवार कार्यकारी जनशक्ति का विवरण

क्षेत्र	मुख्य श्रमिक (हजार में)	प्रतिशत दर
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	176,979	56.6
खनन और उत्खनन	1,908	0.6
विनिर्माण	41,848	13.4
विद्युत गैस और जलआपूर्ति	1,546	0.5
निर्माण	11,583	3.7
थोक, खुदराव्यापार और मरम्मत कार्य, होटल और रेस्तराँ	29,333	9.4
यातायात, भण्डारण और संचार	12,535	4.0
वित्तीय मध्यस्थता, रीयल एस्टेट व्यापार गतिविधियाँ	6,109	2.0
अन्य सेवाएँ	13,131	10.0

कुल मुख्य श्रमिक	312,972	100
------------------	---------	-----

स्रोत-नमूना के आधार पर औद्योगिक वर्गीकरण डेटा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) और GDP (%) की तिमाहीवार वृद्धि

क्षेत्र	2018-2019				2019-2020	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
मूल मूल्यों पर GVA	7.7	6.9	6.3	5.7	4.9	4.3
कृषि, वन एवं मत्स्य	5.1	4.9	2.8	-0.1	2.0	2.1
उद्योग	9.8	6.7	7.0	4.2	2.7	0.5
सेवाएं	7.1	7.3	7.2	8.4	6.9	6.8
बाजार मूल्यों पर GDP	8.0	7.0	6.6	5.8	5.0	4.5

स्रोत- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान (2009-10)

क्षेत्र	स्थिर मूल्य पर	चालू मूल्य पर
1. कृषि	14.65	17.76
2. उद्योग	30.18	27.47
3. सेवा क्षेत्र	55.17	54.77
कुल	100.00	100.00

स्रोत-GVA basic price

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ई0 सन् के प्रारम्भ से विदेशी आक्रमणों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में अधिपत्य था लेकिन इसी चमक ने विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित किया परिणामस्वरूप भारत ने अनेक आक्रमण सहन किये। आक्रमणकारियों ने अपने लाभ हेतु यहाँ के साधनों का विदोहन और लूट की, जिसने सम्पूर्ण व्यवस्था को तबाह कर दिया। अर्थव्यवस्था की वर्तमान अनेक समस्याएँ उसी समय से चली आ रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि क्षेत्र पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर कृषि आज भी आधी आबादी की जीविका का आधार है वहीं सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगातार घटता जा रहा है, जो आजादी के समय से भी लगभग आधा रह गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। उद्योग और निर्माण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से वृद्धि कम हुई है। वहीं कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घटता जा रहा है जिससे कृषि कार्य में संलग्न श्रम शक्ति की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। अनेक किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। यह चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी काल में लगभग सभी व्यवसायिक क्षेत्रों की विकास दर या तो घटी या ऋणात्मक हुई। वहीं कृषि क्षेत्र की विकास दर विगत वर्षों की तुलना में बढ़ी, साथ ही शहरों से बेरोजगार हुए मजदूरों का भार भी कृषि क्षेत्र ने ही उठाया है।

सुझाव

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु विपणन क्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विस्तार कर खाद्य उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कृषि उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा एवं कृषि क्षेत्र में लगे

व्यक्तियों की आय बढ़ेगी। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन सृजित होंगे। आधी आबादी की आय बढ़ने से उद्योग और सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. CMIE Report Dec 2020.
2. NSSO/CSO Report 2009-10.
3. GVA, Basic price 2019-20 Registrar General & Census Commissioner office, Home ministry, Govt. Of India.
4. Maddison, Angus: The World Economy. A Millennial perspective (Vol. 1)
5. Historical Statistics (Vol. 2) OECD 2006, ISBN 92-64-02661-9
6. Maddison Angus (2007) "Contours of the World economy, 1- 2031 AD. Essays in Macro-Economic History", Oxford University press ISBN 978-0-19-922721-1
7. Pravar Sahoo, No easy task for India's labour reforms East Asia Forum 12 Nov 14, EIG (Institute of Economic Growth)
8. Alakh N.Sharma (2006) Flexibility employment and labour market reforms in India 'Economic and Political weekly, 41(21), 2078-2085
9. How India got its funk, the Economist (22 August 2013)
10. Unemployment statistics: www. labour, gov. in ministry of labour and employmet, retrieved 9 Nov. 2018

Abbreviation

1. NITI - National Institution of Transforming India.
2. CSO - Central Statistics Office.
3. NSSO - National Sample Survey Office
4. CMIE - Centre for Monitoring Indian Economy
5. FDI - Foreign Direct Investment.
6. GVA - Gross Value Added.
7. GDP - Gross Domestic Product.